E-ISSN: 2664-603X
P-ISSN: 2664-6021
IJPSG 2021; 3(1): 102-104
www.journalofpoliticalscience.com
Received: 01-10-2021
Accepted: 03-12-2021

डॉ. मनीषा सिंह
विभागाध्यक्ष–राजनीति विज्ञान विभाग, रणवीर राज्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अमेठी, उत्तर प्रदेश, भारत

Corresponding Author:
डॉ. मनीषा सिंह
विभागाध्यक्ष–राजनीति विज्ञान विभाग, रणवीर राज्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अमेठी, उत्तर प्रदेश, भारत

स्वच्छ भारत अभियान–नीतियॉ और चुनौतियॉ

डॉ. मनीषा सिंह

सारांश
स्वच्छ भारत अभियान की शुरूआत 02 अक्टूबर 2014 को गॉधी जयंती के शुभ अवसर पर हुई। इस अभियान का लक्ष्य गॉधीजी की 150वीं जयंती तक पूरे देश को स्वच्छ बनाने का द्रढ़ संकल्प लिया गया। इस क्रम में केन्द्रीय मंत्रीमण्डल ने 'शहरी क्षेत्रों के लिए स्वच्छ भारत मिशन' कार्यक्रम को 24 सितम्बर को स्वीकृति भी दे दी। मिशन के तहत कुल 4041 सांविधिक नगरों में 5 वर्षो तक चलने वाले इस कार्यक्रम की अनुमानित लागत 62,009 करोड़ रूपये होगी। जिसमें केन्द्रीय सहायता 14,623 करोड़ रूपये की होगी और यह उद्देश्य व्यक्तिगत, निर्माण के माध्यम से हासिल किया जाना है। निर्मल भारत अभियान का उद्देश्य सम्पूर्ण स्वच्छता के द्वारा गॉवों में रह रहे लोगों के जीवन में बदलाव लाना है।

मूल शब्दः स्वच्छ भारत, अभियान, नीतियॉ, व्यक्तिगत

प्रस्तावना
स्वच्छ भारत अभियान को मुख्यतः दो भागों में विभाजित करके देखना अधिक सुगम होगा। प्रथम शहरी क्षेत्र द्वितीय ग्रामीण क्षेत्र। 1.04 करोड़ परिवारों को लक्षित करते हुए 2.5 लाख सामुदायिक 2.6 लाख सार्वजनिक सुविधा और प्रत्येक शहर में एक ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन की सुविधा प्रदान करना है। इस कार्यक्रम के तहत आवासीय क्षेत्रों में जहॉ व्यक्तिगत घरेलू क्षेत्र का निर्माण करना मुश्किल है वहॉ पर्यटन स्थलों, बाजारों, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशनों जैसे प्रमुख स्थानों पर भी सार्वजनिक साफ सफायी की व्यवस्था किया जाये। यह कार्यक्रम पॉच साल अवधि में 4401 शहरों में लागू किया जाएगा।
निर्मल भारत अभियान कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा ग्रामीण क्षेत्र में लोगों के लिए मॉग आधारित केन्द्रित अभियान है, जिसमें लोगों की स्वच्छता सम्बन्धी आदतों को बेहतर बनाना, स्वच्छता सुविधाओं की मॉग उत्पन्न करना और स्वच्छता सुविधाओं को उपलब्ध कराना है जिससे ग्रामीणो के जीवन स्तर को बेहतर बनाया जा सके।
बदल रही मानसिकता बहुत महत्वपूर्ण है। चूँकि अधिकतर आईईसी (सूचना शिक्षा एवं संचार) कोश राज्यों के पास है, इसलिए राज्य सरकारो को छात्रों, आशा कार्यकर्ताओं, ऑगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, चिकित्सकों, शिक्षकों, प्रखंड संयोजकों आदि के माध्यम से अंतर्व्यक्ति संचार (आईपीसी) पर अपना ध्यान केन्द्रित करना होगा। इसके लिए इन्हें घर–घर भी सम्पर्क करना होगा। लघु फिल्मों की सीडी, टेलीविजन, रेडियो, डिजिटल सिनेमा, पंफलेट के उपयोग भी करने होंगे।
स्वच्छ भारत अभियान का मोदी सरकार के स्वच्छ भारत अभियान में जहॉ तक गॉवों का प्रश्न है, इसे निर्मल भारत अभियान की सफलता के साथ जोड़ कर ही देखा जाता रहा है। निर्मल भारत अभियान का उद्वेश्य सम्पूर्ण स्वच्छता के द्वारा गॉवों में रह रहे लोगों के जीवन में बदलाव लाना है । ऐसा माना जा रहा है कि 2022 तक हम निर्मल भारत का निर्माण कर सकेंगे। ग्राम पंचायत के जरिये ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबन्धन के साथ गॉव को साफ रखे जाने की योजना है। मांग के आधार पर सभी घरों को नलों के साथ जोड़ कर सभी गॉव में पानी पाइप लाइन 2019 बिछाये जाने है। भारत में 1.21 अरब लोग रहते है और दुनिया की आबादी का छठा हिस्सा यहॉ निवास करता है। देश में 1980 के दशक की शुरूआत में स्वच्छता अवृत्ति क्षेत्र 1 प्रतिशत जितना कम था। 2011 की जनगणना के हिसाब से 16.58 करोड़ घरों की लगभग 72.2 प्रतिशत भारतीय जनसंख्या 6,38,000 गॉव में रहती है। जिसका मतलब है कि देश के 67.3 प्रतिशत घरों की पहुँच अभी तक स्वच्छता सुविधा तक नहीं हो पायी है। राज्यों के माध्यम से पेय जल एवं स्वच्छता मंत्रालय से कराये गये आधारभूत सर्वेक्षण 2012–13 के अनुसार पाया गया है। स्वच्छ भारत का सपना संजोये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गॉधी की जयंती पर अपने ड्रीम प्रोजेक्ट स्वच्छ भारत अभियान की शुरूआत की। स्वच्छ भारत अभियान या 'क्लीन इण्डिया कैम्पेन' देश का सबसे बड़ा स्वच्छता अभियान है।

प्रधानमंत्री ने हर भारतीय से इस मिशन में शामिल होकर इसे सफल बनाने की अपील की है। स्वच्छ भारत मिशन एक बड़े पैमाने पर जन आन्दोलन है जिसका प्रयास 2019 तक भारत को स्वच्छ बनाना है। इस मिशन में सभी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को शामिल किया गया है।

प्रस्तुत शोध पत्र चार खण्डों मे विभाजित है। प्रथम खण्ड में अभियान का परिचय तथा द्वितीय खण्ड अभियान का प्रारूप व क्रियान्वयन तृतीय खण्ड अभियान की चुनौतियों को प्रस्तुत करता है। खण्ड चार निष्कर्ष व अभियान को सफल करने के सुझाव को प्रस्तुत करना है।

स्वच्छ भारत अभियान को मुख्यतः दो भागों में विभाजित करके देखना अधिक सुगम होगा। प्रथम शहरी क्षेत्र द्वितीय ग्रामीण क्षेत्र 1.04 करोड़ परिवारों को लक्षित करते हुए साफ की व्यवस्था प्रदान की गयी है। सर्वाजनिक स्थल को स्वच्छ रखना और प्रत्येक शहर में एक ठोस अपशिष्ट की सुविधा प्रदान करना है। इस कार्यक्रम के तहत आवासीय क्षेत्रों में जहॉ व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों का निर्माण करने की योजना है वहीं पर्यटन स्थलों, बाजारों, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशनों जैसे प्रमुख स्थलों पर भी सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण किया जायेगा। यह कार्यक्रम पॉच साल की अवधि में 4401 शहरो में लागू किया जायेगा। निर्मल भारत अभियान कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा ग्रामीण क्षेत्र में लोगों के लिए मांग आधारित केन्द्रीत अभियान है।

मानव संशाधन विकास मंत्रालय के अधीन स्वच्छ भारत, स्वच्छ विद्यालय अभियान केन्द्रीय 25 सितम्बर 2014 से 31 अक्टूबर 2014 के बीच केन्द्रीय विद्यालयो एवं नवोदय विद्यालय संगठन में आयोजित किया गया।

- स्कूल कक्षाओं के दौरान प्रतिदिन बच्चों के साथ सफायी और स्वच्छता के विभिन्न पहलुओं पर विशेष रूप से महात्मा गॉधी की स्वच्छता और अच्छे स्वास्थ्य से जुड़ी शिक्षाओं के सम्बन्ध में बाते करें।
- कक्षा, प्रयोगशला और पुस्तकालयों आदि की सफाई करना
- स्कूल में स्थापित किसी भी मूर्ति या स्कूल की स्थापना करने वाले व्यक्ति के योगदान के बारे में बात करना और इस मूर्तियों की सफाई करना।
- रसोई और सामान गृह की सफाई करना।
- खेल के मैदान की सफाई करना।
- स्कूल बागीचों का रख–रखाव और सफाई करना।
- स्कूल भवनों का वार्षिक रखरखाव रंगाई एवं पुताई के साथ।
- निबन्ध, वाद–विवाद, चित्रकला सफाई और स्वच्छता पर प्रतियोगिताओं का प्रयोजन बाल मंत्रीमण्डलों का निगरानी दल बनाना और सफाई अभियान की निगरानी करना।
- केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार सारी भारत में हर साल 47 मिलियन टन ठोस कचड़ा उत्पन्न होता है। इसके अतिरिक्त यह भी बताया गया है कि 75 प्रतिषत से ज्यादा सीवेज का निपटारा नही होता है। ठोस कचरे की रिसाइकलिंग की भी एक बड़ी समस्या है। भविष्य में बडी समस्याओं से बचने के लिए इन मुद्दों का निपटारा आज किया जाना जरूरी है।
- एक अन्य बड़ी चुनौती लोगों की सोच बदलना है। हमारे देश के लोग कचरा सड़क पर फेकना कब सिखेंगेघ्या लोग खुद को और अपने इलाके को साफ करना कब सिखेंगेघ
- ग्रामीण भारत में साफ–सफाई की कमी एक बड़ी चुनौती है। स्वच्छता के कमी की समस्या इतनी विकराल है कि 2019 तक प्रधानमंत्री का लक्ष्य पूरा हो पायेगा इसमें संदेह है।
- बदल रही मानसिकता बहुत महत्वपूर्ण है। चूँकि अधिकतर आईईसी (सूचना शिक्षा एवं संचार) कोश राज्यों के पास है। इसलिए राज्य सरकारों को छात्रों, आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकताओं, चिकित्सकों, शिक्षकों, अखण्ड संयोजकों आदि के माध्यम से अर्न्तव्यक्ति संचार (आईपीसी) पर अपना ध्यान केन्द्रित करना होगा। इसके लिए उन्हें घर–दर–घर भी सम्पर्क करना होगा लघु फिल्मो की सीडी, टेलीविजन, रेडियो, डिजिटल सिनेमा का उपयोग भी करना होगा।

सुरक्षित स्वच्छता व्यवहार के प्रति अपनी मानसिकता में बदलाव लाने के लिए स्थानीय एवं राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों/सिनेमा की हस्तियों की भी इस अभियान में भागीदारी जरूरी है। पाइपलाइन जल आपूर्ति एवं घरों में शौचालय के लिए जिला स्तरीय सामेकित डीपीआर (डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स) के जरिए एकदम निचले स्तर की योजना में पानी और स्वच्छता दोनों को एक साथ शामिल करना होगा। इसके लिए राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति की मंजूरी लेनी होती है।

यदि हम अपने घरों के पीछे सफाई नहीं रख सकते तो स्वराज की बात बेईमानी होगी। हर किसी को स्वयं अपना सफाईकर्मी होना चाहिए। प्रखंड संयोजक एवं स्वच्छता दूत अब अनुबन्ध के आधार पर भर्ती किए जा रहे हैं एवं लोगों के प्रोत्साहन सूचना के प्रसार के लिए एनजीओ, स्वयं सहायता समूह, स्कूल छात्र, स्थानीय महिला समूह आदि के जरिए अंतवैयक्तिक संचार के नए तरीकों का पता लगाया जा सकता है। मिशन के भीतर कम्पनी अधिनियम के अंतर्गत एक कम्पनी के रूप में एसपीवी (विशिष्ट उद्देश्य वाहन) स्थापित किये जाने की योजना है। सीएसआर, कोश, सरकारी एवं गैर सरकारी कोशों के अलावा एक बाहरी स्रोत होगा एवं सीएसआर परियोजना को लागू करेगा। यह केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा दिये गये जल एवं स्वच्छता के लिए विशिष्टता प्राप्त पीएमसी के रूप में भी काम करेगा। यह राजस्व स्रोतों, सामुदायिक जल उपचार संयंत्रों आदि मामलों में भी काम करेगा। जल एवं स्वच्छता के लिए कई जिलों में काम करने वाली बहु ग्रामीण पाइपलाइन परियोजनाओं के लिए राज्यों द्वारा जिला डीपीआर की तैयारी के लिए पीएमसी (प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट) की जरूरत पड़ने पर नौकरियों पर भी रख सकेगा। केन्द्र/राज्यों द्वारा भुगतान के आधार पर एक पीएमसी के रूप में आईईसी/आईपीसी गतिविधियों को भी अपने हाथ में ले सकता है। आधारभूत सर्वेक्षण 2013 में, राज्यों ने बताया है कि देश में निम्नलिखित स्वच्छता सेवा उपलब्ध कराने की आवष्यकता है।

तालिका 1: घटक संख्या

घटक	संख्या
भारत में कुल घरों की संख्या	17.13 करोड़
आईएचएचएल	11.11 करोड़
विद्यालय में शौचालय	56,928
ऑगनवाड़ी शौचालय	1,07,695
सामुदायिक स्वच्छता परिसर	1,14,315

(इनमें से केवल 8,84,39,786 ही पात्र क्षेणी के अन्तर्गत है)

इस प्रकार स्वच्छ भारत/निर्मल भारत अभियान योजना के अंतर्गत अगले पॉच सालों में 2019 तक प्रतिवर्ष 177 लाख की दर से 8.84 करोड़ परिवारों को प्रोत्साहन दिया जाना है। इस समय परिवारों में शौचालय की वृद्धि दर 3 प्रतिशत है जिसे स्वच्छ भारत के जरिये 2022 तक तीन गुना से ज्यादा बढ़ाकर 10 प्रतिशत तक की उपलब्धि पर ले जाना है। इस समय 14,000 शौचालय प्रतिदिन बनाये जा रहे है। इस योजना में शौचालय निर्माण दर 48,000 तक प्रतिदिन करना है। नाबार्ड/सिडबी के सहयोग से 2.27 करोड़ शौचालय (एपीएल श्रेणी के अन्तर्गत) और बनाये जाने है।

स्वच्छ भारत अभियान निःसन्देह भारत सरकार द्वारा उठाया गया

एक सराहनीय कदम है। इस अभियान को सफल तभी बनाया जा सकता है जब स्वच्छता मानव की मूल प्रवृत्ति में शामिल हो। इसके लिए प्रत्येक नागरिक को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। इसकी शुरूआत समान की सबसे छोटी इकाई परिवार से प्रारम्भ होकर विद्यालय, महाविद्यालय समाज, सार्वजनिक स्थानों व फैक्टरियों तक होनी चाहिए। फैक्टरियों में ऐसी तकनीकों को अपनाया जाए जिससे वहॉ से निकलने वाला वेस्ट मटेरियल दोबारा रिसाइकलिंग के द्वारा प्रयोग में लाया जा सके। समाज में विद्यमान विशिष्टजन खेलों से सम्बन्धित लोकप्रिय खिलाड़ी सिनेमा के बड़े सेलेब्रिटीज तथा राजनीति के चर्चित हस्तियॉ अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं तथा समाज के प्रत्येक वर्ग को स्वच्छता के प्रति जागरूक कर सकते हैं इसके लिए छोटी फिल्म नुक्कड़ नाटकों आदि का आयोजन सफल प्रयास साबित हो सकता है अन्यथा निष्कर्ष रूम में हम कह सकते हैं कि–

सिर्फ अभियान शुरू करना ही काफी नहीं है, परिणाम मायने रखता है। सिर्फ सरकार इसे सफल नहीं बना सकती, लोगों की भागीदारी सबसे जरूरी है। इस कार्यक्रम के लिए विस्तृत ब्लू प्रिंट बनाना जरूरी है। समग्र तरीके से स्वच्छ भारत अभियान को लागू करने, सरकार और लागों के प्रयासों से आने वाले सालों में भारत अवष्य एक स्वच्छ देश बन सकता है।

सन्दर्भ

1. इंडिया टुडे
2. योजनो
3. कुरूक्षेत्र
4. दैनिक समाचार
5. भाजपा का चुनावी घोषणा पत्र।
6. http://hi.vikaspedia.in/health/sanitation-and-hygiene/
7. http://hi.wikipedia.org/wik
8. http://hindi.indiawaterportal.org/node/48221